52673876
25/01

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांकः–पेंशन विविध/LID- 34142,35274,35801/1241

दिनांक 16-01-2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) Andhra Pradesh

Saifabad Hyderabad 500004

विषयः– 1. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 19/2016/ए–1–907/ दस –2016–100 (65) /2014 दिनांक 14.12.2016.

2. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 शासनादेश संख्या 29/2016/सा–3–606/ दस–2016–308/2016 टी0सी0 दिनांक 24.08.2016.

3. वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या 01/2017/वे0आ0–2–02/ दस–17–01(एम0/2016 दिनांक 03.01.2017.

4627746
01/02/17

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्नः– यथोपरि

oap

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय
O/o. the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
30 JAN 2017
No.........
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
Andhra Pradesh & Telangana
हैदराबाद/Hyderabad - 500 004.

भवदीय

लेखाधिकारी/पेंशन विविध

UP –

संख्या-19/2016/ए-1-907/दस-2016-10(65)/2014

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2016

विषय : प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु शासन के पत्रांक-ए-1-1086/दस-2015-10(65)/2014, दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में आधार कार्ड में अंकित बायोमेट्रिक्स के आधार पर ऑनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना सम्भव होगा। यह व्यवस्था ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए लागू होगी, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध है। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) को जनरेट करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार-पत्र (पीपीओ), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियाँ लेकर उपस्थित होना होगा।

(2) कोषागार स्तर पर www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जीवन प्रमाण एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों का मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर फीड करने पर एक फार्म खुलेगा, जिसमें आधार नम्बर, पेंशनर का नाम, पेंशन प्राधिकार संख्या, बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण एवं मोबाइल नम्बर फीड कर रजिस्टर कराया जायेगा तथा एस0टी0क्यू0सी0 बायोमेट्रिक डिवाइस पर अंगूठा लगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UP_DIGI LIFCERT_VII CPC

कर बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन कराया जायेगा।

(3) उक्त हेतु कोषागार प्रथम बार समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों का मिलान कोषागार में उपलब्ध पेंशनरों के अभिलेखों से करेंगे। बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन होने पर आधार कार्ड की मूलप्रति से मिलान कर आधार कार्ड की छायाप्रति तथा एथेंटिकेशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रति गार्ड फाइल में रखी जोयगी एवं आधार नम्बर का डेटाबेस भी तैयार किया जायेगा।

(4) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) जनरेट करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उनके द्वारा प्रदत्त मोबाइल पर एस एम एस द्वारा ट्रांजेक्शन आईडी प्राप्त होगी। इसके आधार पर पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स कम्प्यूटर जनरेटेड डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) वर्ष के किसी भी माह में दिया जा सकता है।

(5) प्रथम बार कोषागार स्तर पर डिजिटल जीवन प्रमाण हेतु रजिस्टर हो जाने के उपरांत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भविष्य में जीवन प्रमाण-पत्र देने हेतु कोषागार में उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

(6) जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर कोषागार द्वारा www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत कर दिये जायेंगे, वे भविष्य में जीवन प्रमाण-पत्र टैब/स्मार्टफोन/विण्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगर प्रिन्टर स्कैनर का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र दे पायेंगे। इस हेतु वे नजदीकी जीवन प्रमाण-पत्र केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसकी सूची www.jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट के Locate a Centre लिंक में दी गयी है।

(7) कोषागार www.jeevanpramaan.gov.in पर अपना लॉगिन कर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के जीवन प्रमाण-पत्र को उसके द्वारा दिये गये आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर तथा ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर ऐक्सेप्ट/रिजेक्ट कर सकेंगे।

(8) सम्बन्धित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र पोर्टल से डाउनलोड किये गये जीवन प्रमाण-पत्र को अपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय की गार्ड फाइल से मिलान कर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के डाटा बेस को मैनुअली/स्वतः अपडेट कर दिया जायेगा।

(9) डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certficate) की नवीन व्यवस्था वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु वेबसाइट www.jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जा सकता है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था उपरोक्तानुसार लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2016/ए-1-907(1)/दस-2016-10(65)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(5) महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(6) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई।

(7) मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।

(8) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(10) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।

(11) मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ/नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

01.01.2016 के पूर्व

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्याः 29/2016-सा-3-606/दस-2016-308/2016

लखनऊः दिनाँकः 24 अगस्त,2016

कार्यालय - ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के अनन्तर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01-01-2016 से पेंशन पुनरीक्षण/समेकन संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2016-पी०पी० एण्डपी० डब्ल्यू(ए)(ii), दिनॉक 04 अगस्त, 2016 जारी किया गया है, जो केन्द्र सरकार के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 अगस्त, 2016 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा के दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं अवशेषों का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाए।

3- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण तथा एरियर भुगतान की कार्यवाही कोषागार स्तर पर की जायेगी।

4- दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेश निर्गत कर दिये जाने पर, तत्क्रम में पृथक आदेश निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नकः यथोक्त।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्याः29/2016/सा-3-606(1)/दस-2016-308/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

--2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

F.No.38/37/2016-P&PW(A) (ii)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Pension & Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003

Dated the 4th August, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Implementation of Government's decisions on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission - Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc.

The undersigned is directed to say that in pursuance of Government's decision on the recommendations of Seventh Central Pay Commission, sanction of the President is hereby accorded to the regulation, with effect from 01.01.2016, of pension/ family pension of all the pre-2016 pensioners/ family pensioners in the manner indicated in the succeeding paragraphs. Separate orders are being issued in respect of employees who retired/died on or after 01.01.2016.

2.1 These orders shall apply to all pensioners/family pensioners who were drawing pension/family pension before 1.1.2016 under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules and the corresponding rules applicable to Railway pensioners and pensioners of All India Services, including officers of the Indian Civil Service retired from service on or after 1.1.1973. A pensioner/family pensioner who became entitled to pension/family pension with effect from 01.01.2016 consequent on retirement/death of Government servant on 31.12.2015, would also be covered by these orders.

2.2 Separate orders will be issued by the Ministry of Defence in regard to Armed Forces pensioners/family pensioners.

2.3 These orders also do not apply to retired High Court and Supreme Court Judges and other Constitutional/Statutory Authorities whose pension etc. is governed by separate rules/orders.

3. In these orders :

a. 'Existing pensioner' or 'Existing Family pensioner' means a pensioner/family pensioner to whom these orders are applicable in terms of para 2.1 above.

b. 'Existing pension' or 'Existing Family Pension means the basic pension (inclusive of commuted portion, if any) or basic family pension, as had been fixed at the time

of implementation of 6th CPC recommendations, which an existing pensioner or family pensioner was entitled to.

4.1 For existing pensioners, who have retired before 01.01.2016, the revised pension/family pension with effect from 01.01.2016 shall be determined by multiplying the pension/family pension, as had been fixed at the time of implementation of 6th Central Pay Commission (CPC) recommendations, by 2.57. The amount of revised pension/family pension so arrived at shall be rounded off to next higher rupee.

Illustration:

Case I

Pensioner 'A' retired at last pay drawn of Rs. 79,000 on 31st May, 2015 under the 6th CPC regime in the scale of Rs. 67000-79000:

		Amount in Rs.
1.	Basic Pension fixed in 6th CPC	39500
2.	Revised Pension fixed under 7th CPC (using a multiple of 2.57)	101515

Case II

Pensioner 'B' retired at last pay drawn of Rs. 4,000 on 31st January, 1989 under the 4th CPC regime in the pay scale of Rs. 3000-100-3500-125-4500:

		Amount in Rs.
1.	Basic Pension fixed in 4th CPC	1940
2.	Basic Pension as revised in 6th CPC	12600
3.	Revised Pension fixed under 7th CPC (using a multiple of 2.57)	32,382

4.2 For this purpose, the existing pension/family pension will be the basic pension/family pension only without the element of additional pension available to the old pensioners/family pensioners of the age of 80 years and above. The additional pension/family pension payable to the old pensioners/family pensioners will be worked out in accordance with para 4.5 of this O.M.

4.3 Since the consolidated pension will be inclusive of commuted portion of pension, if any, the commuted portion will be deducted from the said amount while making monthly disbursements.

4.4 The minimum pension with effect from 01.01.2016 will be Rs. 9000/- per month (excluding the element of additional pension to old pensioners). The upper ceiling on pension/family pension will be 50% and 30% respectively of the highest pay in the Government (The highest pay in the Government is Rs. 2,50,000 with effect from 01.01.2016).

4.5 The quantum of pension/family pension available to the old pensioners/ family pensioners shall continue to be as follows:-

Age of pensioner/family pensioner	Additional quantum of pension
From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/ family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension / family pension
From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic pension / family pension
From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic pension / family pension
100 years or more	100% of revised basic pension / family pension

The amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order. For example, in case where a pensioner is more than 80 years of age and his/her revised pension in terms para 4.1 above is Rs.10,000 pm, the pension will be shown as (i).Basic pension=Rs.10,000 and (ii) Additional pension = Rs.2,000 pm. The pension on his/her attaining the age of 85 years will be shown as (i).Basic Pension = Rs.10,000 and (ii) additional pension = Rs.3,000 pm. Dearness relief will be admissible on the additional pension available to the old pensioners also.

4.6 The revised pension/family pension arrived at as per paragraph 4.1 includes dearness relief sanctioned from 1.1.2016.

5. Where the revised pension/family pension in terms of paragraph 4.1 above works out to an amount less than Rs. 9000/-, the same shall be stepped up to Rs. 9000/-. This will be regarded as pension/family pension with effect from 1.1.2016.

6. The existing instructions regarding regulation of dearness relief to employed/re-employed pensioners/family pensioners, as contained in Department of Pension & Pensioners Welfare O.M. No. 45/73/97-P&PW(G) dated 02.07.1999, as amended from time to time, shall continue to apply.

7. The cases of Central Government employees who have been permanently absorbed in public sector undertakings/autonomous bodies will be regulated as follows:-

(a) PENSION

Where the Government servants on permanent absorption in public sector undertakings/autonomous bodies continue to draw pension separately from the Government, the pension of such absorbees will be updated in terms of these orders. In cases where the Government servants have drawn one time lump sum terminal benefits equal to 100% of their pensions and have become entitled to the restoration of one-third commuted portion of pension as per the instructions issued by this Department from time to time, their cases will not be covered by these orders. Orders for regulating pension of such pensioners will be issued separately.

ul.

(b) FAMILY PENSION

In cases where, on permanent absorption in public sector undertakings/autonomous bodies, the terms of absorption and/or the rules permit grant of family pension under the CCS (Pension) Rules, 1972 or the corresponding rules applicable to Railway employees/members of All India Services, the family pension being drawn by family pensioners will be updated in accordance with these orders.

8. The matter regarding Constant Attendant Allowance admissible to the existing pensioners shall be examined by a Committee comprising Finance Secretary and Secretary (Expenditure) as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Posts, Health & Family Welfare, Personnel & Training and Chairman, Railway Board as Members. Till a final decision is taken based on the recommendations of the Committee, Constant Attendant Allowance shall be paid at existing rates.

9. All Pension Disbursing Authorities including Public Sector Banks handling disbursement of pension to the Central Government pensioners are hereby authorised to pay pension/family pension to existing pensioners/family pensioners at the revised rates in terms of para 4.1 and 5 above without any further authorisation from the concerned Accounts Officers/Head of Office etc. Wherever the age of pensioner/ family pensioner is available on the pension payment order, the additional pension/ family pension in terms of para 4.4. above may also be paid by the pension disbursing authorities immediately without any further authorisation from the concerned Account Officer/ Head of Office, etc. A suitable entry regarding the revised pension shall be recorded by the pension Disbursing Authorities in both halves of the Pension Payment Order.

10 The pension/family pension as worked out in accordance with provisions of Para 4.1. and 5 above shall be treated as 'Basic Pension' with effect from 01.01.2016. The revised pension/family pension includes dearness relief sanctioned from 1.1.2016 and shall qualify for grant of Dearness Relief sanctioned thereafter.

11. Further orders in regard to revision of pension based on the recommendations of the Committee to be constituted in terms of the Government's decision on Item No. 11 of this Department's Resolution No. 38/37/2016-P&PW (A) dated 4th August, 2016, will be issued in due course.

12. After a decision as in para 11 above is taken by the Government and orders are issued in this regard, the Head of the Department of the Ministry, Department, Office, etc. from which the government servant had retired or where he was working prior to his demise will revise the pension/family pension of all pensioners/ family pensioners with

effect from 1st January 2016 in accordance with those orders and issue revised Pension Payment Order (PPOs) accordingly.

13. It is considered desirable that the benefit of these orders should reach the pensioners as expeditiously as possible. To achieve this objective it is desired that all Pension Disbursing Authorities should ensure that the revised pension and the arrears due to the pensioners in terms of para 4.1. and para 5 above is paid to the pensioners or credited to their account by 31st August, 2016 or before positively.

14. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

15. Ministry of Agriculture etc. are requested to bring the contents of these Orders to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached and subordinate Offices under them on a top priority basis. All pension disbursing offices are also advised to prominently display these orders on their notice boards for the benefit of pensioners.

16. Hindi version will follow.

(Vandana Sharma)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/ Departments of Government of India

Copy to : As per mailing list

- Central Pension Accounting Office, New Delhi

-CMDs of All Pension Disbursing Banks

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या– 01 /2017/वे0आ0–2–02 /दस–16–01(एम)2016
लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों पुनरीक्षण के संबंध में विचार कर संस्तुति देने हेतु शासकीय संकल्प सं0–38/2016/वे0आ0–2–876/दस–01(एम)/2016, दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा श्री जी0 पटनायक, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन किया गया है। वेतन समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों के सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानों के साथ–साथ पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति दी जा चुकी है।

2– वेतन समिति द्वारा अभी विभिन्न श्रेणी के सामान्य कोटि के पदों के साथ–साथ राजकीय विभागों के विभिन्न श्रेणी के पदों तथा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं आदि के संबंध में संस्तुतियाँ दिया जाना शेष है। अतः राज्यपाल महोदय वेतन समिति का कार्यकाल 01–03–2017 से अगले 06 माह अर्थात दिनांक 31–08–2017 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2 /दस–16–01(एम)2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अध्यक्ष, वेतन समिति।
3– सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश।
4– प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
5– प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
6– वित्त(सामान्य)अनुभाग–1/2/3.
7– नियुक्ति अनुभाग–1.
8– इरला चेक अनुभाग।
9– मुख्य कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10– वित्त (सेवायें) अनुभाग–1/4.
11– लेखाकार–कम–कोषाध्यक्ष, वेतन समिति।

आज्ञा से,

(...मेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।